ग्रीन–फील्ड मेगा लेदर क्लस्टरों की स्थापना तेजी से की जाएगी

- *मुख्य सचिव– मेगा लेदर क्लस्टरों के विकास का कार्य गति लाई जाए*
- *नवीन अवस्थापना एवं औद्योगिक नीति में विद्यमान सभी सुविधायें होंगी उपलब्ध*

लखनऊ, 11 दिसम्बर 2012

जनपद हरदोई में सण्डीला और कानपुर नगर के रमईपुर क्षेत्र में प्रस्तावित मेगा लेदर क्लस्टरों के विकास में तेजी लाई जाएगी। मुख्य सचिव, जावेद उस्मानी ने आज एक उच्च–स्तरीय बैठक में इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाने के निर्देश दिए। इन परियोजनाओं के परामर्शी आईएलएफएस लि. ने लेदर क्लस्टरों के विकास के लिए आवश्यक कार्यवाही पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया।

मुख्य सचिव ने कहा– ***"नवीन अवस्थापना एवं औद्योगिक नीति में निर्दिष्ट सभी सुविधाओं का उपयोग कर इन परियोजनाओं को विकसित किया जाए।"***

उन्होंने कहा कि क्योंकि इन लेदर क्लस्टरों में रु. 200 करोड़ से अधिक के निवेश की सम्भावना है अतः नीति में सम्मिलित मेगा परियोजनाओं को उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाया जाना चाहिए।

एक मेगा लेदर क्लस्टर पार्क जनपद हरदोई में सण्डीला औद्योगिक क्षेत्र की लगभग 300 एकड़ भूमि में स्थापित किया जाएगा। जबकि दूसरा पार्क कानपुर नगर के रमईपुर क्षेत्र में ग्राम कुरैना बहादुरनगर तथा सेनपूरबपारा में कुल 625 एकड़ जमीन पर बनाने की योजना है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी), अनिल कुमार गुप्ता ने कहा– *"परियोजनाओं को चमड़ा व्यवसाइयों से बहुत समर्थन प्राप्त हुआ है। लगभग 170 टैनरी मालिकों ने सण्डीला में तथा 300 टैनरियों ने कानपुर में अपनी इकाइयाँ स्थापित करने के लिए आवेदन किया है।*

प्रस्तावित लेदर पार्कों में विश्व–स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं के साथ–साथ आधुनिकतम तकनीक से सुसज्जित उत्पादन सयंत्रों को विकसित किया जाएगा जिससे स्वदेशी मांग और निर्यात मापदण्डों को पुरा किया जा सके।

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश के पारम्परिक चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने और विद्यमान चमड़ा उद्योग इकाइयों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव ने राज्य में दो नवीन मेगा लेदर क्लस्टर पार्कों की स्थापना को अपनी सैद्धान्तिक सहमति पहले ही प्रदान कर दी है।

प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण संरक्षण के लिए उद्योगों द्वारा निर्गत अपशिष्ट व उत्प्रवाही स्राव के लिए शोधक संयत्र स्थापित किए जाएंगे। वर्षा जल संचयन, वेयरहाउसिंग, कच्चे माल के बैंक, प्रदर्शनी केन्द्र, डिज़ाइन केन्द्र, मानव संसाधन विकास आदि के प्राविधान भी इन लेदर पार्कों में प्रस्तावित हैं।

प्रत्येक पार्क में लगभग 1000 करोड़ रुपये का निवेश अपेक्षित है जिससे करीब **10,000 व्यक्तियों को रोजगार** मिल सकेगा।

यूपीएसआइडीसी के प्रबन्ध निदेशक मनोज सिंह ने बताया कि इन मेगा लेदर क्लस्टर पार्कों का क्रियान्वयन स्पेशियल पर्पज़ व्हिकिल (special purposes vehicle) के माध्यम से भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत किया जाएगा। इस योजना के तहत पार्क की स्थापना में 70 प्रतिशत योगदान भारत सरकार का होगा। भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ इण्डस्ट्रियल पॉलिसी एण्ड प्रोमोशन (DIPP) प्रत्येक 150 एकड़ भूमि पर बनाये जाने वाले क्लस्टर के लिए अधिकतम रु. 150 करोड़ का अनुदान दिया जाता है।

उन्होंने बताया कि शीघ्र ही इन मेगा लेदर क्लस्टरों के लिए DIPP में प्रस्ताव भेजे जाएंगे।